



रखीना टंडन की तमिल सिनेमा में वापसी

▶ पेज -7

DBD दो बजे दोपहर

पत्रकारिता पावर नहीं रिसासिबिलिटी है



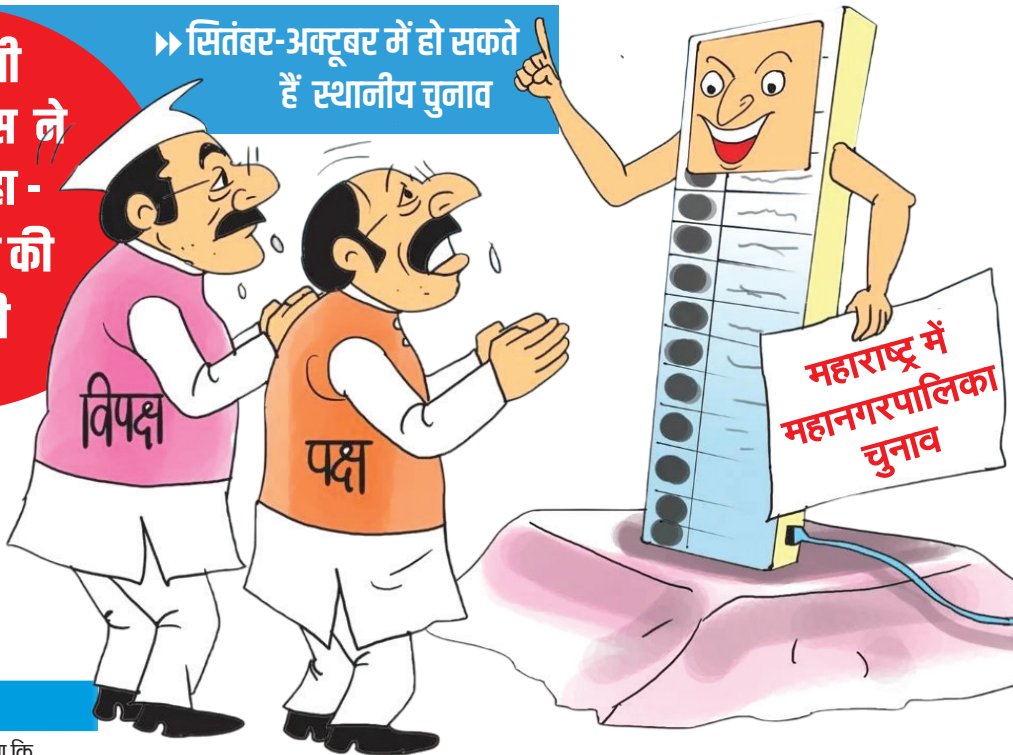
पाकिस्तान को फिर FATF की ग्रे लिस्ट में लाएंगे : सरकार

▶ पेज -8

सीएम फडणवीस का चुनावी बिगुल

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया एलान, कहा - अब दूसरी परीक्षा की तैयारी करनी है

▶ सितंबर-अक्टूबर में हो सकते हैं स्थानीय चुनाव



उद्धव सरकार पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र में उद्धव सरकार थी, तो राज्य के सभी निर्माण कार्य ठप हो गए थे, जिससे जनता में नाराजगी फैल गई थी। इसी नाराजगी के चलते लोगों ने विधानसभा चुनाव में उद्धव सरकार का रास्ता बंद कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बड़ी हलचल

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि महाराष्ट्र में सभी लंबित स्थानीय निकाय चुनाव चार महीने के भीतर कराए जाएं। इसके बाद राज्य की सभी प्रमुख पार्टियां, विशेष रूप से महायुति, महाविकास आघाड़ी और निर्दलीय गुट, चुनावी मोड़ में आ गए हैं।

वार्ड गठन की प्रक्रिया शुरू

महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय निकाय चुनावों के संबंध में वार्ड गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने बताया कि वार्ड गठन की प्रक्रिया में करीब 70 दिन लगेंगे। इसके बाद आरक्षण होगा, जिसमें 15 दिन और लगेंगे। मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया में 40 दिन और लगेंगे।

प्रशासकों के अधीन हैं नगर निगम

सभी 29 नगर निगमों, 248 नगर परिषदों, 42 नगर पंचायतों, 32 जिला परिषदों और 336 पंचायत समितियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और ये वर्तमान में प्रशासकों के अधीन हैं। 27 नगर निगमों का कार्यकाल 2020-2023 के बीच समाप्त हो गया।

ब्रीफ न्यूज़

गढ़चिरोली में पुलिस से मुठभेड़ में चार हार्डकोर नक्सली ढेर

गढ़चिरोली। महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित नव-स्थापित कावेड थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें गढ़चिरोली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने चार हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराने में सफलता पाई है। यह घटना महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस की लगातार सक्रियता और नक्सल विरोधी अभियानों का नतीजा है। हालांकि अभी तक मारे गए नक्सलियों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस बल ने पुष्टि की है कि वे हार्डकोर नक्सली थे, जो कई गंभीर अपराधों में वांछित थे। यह मुठभेड़ कावेड और नेतगुंडा से इंद्रावती नदी के किनारे के इलाके में भारी बारिश के दौरान हुई। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, पुलिस दल ने बहादुरी से नक्सलियों का सामना किया और उन्हें मार गिराने में सफलता हासिल की।

ढाई साल बाद दिव्यांग विभाग को मिला स्वतंत्र मंत्री

मुंबई। प्रदेश के दिव्यांग कल्याण विभाग को लगभग ढाई साल बाद स्वतंत्र कैबिनेट मंत्री मिले हैं। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल सावे को दिव्यांग कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सावे के पास अभी ओबीसी कल्याण, दुग्ध विकास और अपारंपरिक ऊर्जा विभाग है। फिलहाल दिव्यांग कल्याण विभाग का प्रभार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास था। लेकिन अब सावे राज्य के नए दिव्यांग कल्याण मंत्री होंगे। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। राज्य में 15 दिसंबर 2022 की अधिसूचना के जरिए स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी।

अस्पतालों से गैरहाजिर 58 मेडिकल अफसरों की सेवा समाप्त



डीबीडी संवाददाता | मुंबई

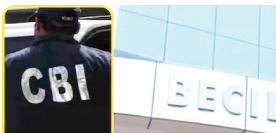
स्वास्थ्य विभाग ने प्रोबेशन अवधि के दौरान बिना वैध कारण के अस्पतालों से एक वर्ष से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले 58 मेडिकल अफसरों की सेवा समाप्त कर दी है। शुक्रवार को जारी शासनादेश के अनुसार, इन अफसरों ने सरकार की नियमों का उल्लंघन किया था, विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी सेवाएं खत्म कर दीं। मेडिकल अफसरों पर सामान्य प्रशासन विभाग के फरवरी 2016 के निर्णय के तहत प्रोबेशन नीति लागू होती है। इसमें कहा गया है कि प्रोबेशन अवधि के दौरान यदि कोई अधिकारी बिना वैध कारण 7 दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। इन 58 अफसरों ने एक वर्ष से अधिक समय तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति दर्ज कराई थी।

बीईसीआईएल लोन घोटाला

नोएडा से मुंबई तक फैला घूस का जाल

एजेंसी | मुंबई/नई दिल्ली

बीईसीआईएल (ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड) में 58.60 करोड़ रुपए के लोन घोटाले के सनसनीखेज खुलासे से देश हिला हुआ है। अब सीबीआई ने इस मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। आरोप है कि करोड़ों की रिश्ता ली और फजी दस्तावेजों के सहारे बैंक के पुर्व सीएमडी जोर्ज कुरुविला, जीएम डब्ल्यू। प्रसाद, लीगल एडवाइजर आशीष प्रताप सिंह और मुंबई स्थित निजी कंपनी TGBL के सीईओ प्रतीक कनकिया को खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है।



फर्जी बैंक गारंटी और दस्तावेजों को किया नष्ट

घोटाले को छुपाने के लिए 25 करोड़ रुपए की नकली बैंक गारंटी (PNB की) पेश की गई। जो जांच में फर्जी साबित हुई। साथ ही BECIL के प्रोजेक्ट से जुड़े दस्तावेज जानबूझकर नष्ट कर दिए गए। इस वजह से BECIL को 58.60 रुपए करोड़ का भारी नुकसान हुआ है। सीबीआई ने मामले में तत्कालीन CMD जोर्ज कुरुविला, G ME डब्ल्यू. प्रसाद और TGBL के CEO प्रतीक कनकिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है।

12 हजार करोड़ की धोखाधड़ी में ईडी की छापेमारी

▶ दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में 15 परिसरों पर जांच
▶ बिल्डरों पर मनी लांड्रिंग का आरोप

एजेंसी | मुंबई/नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में 12,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लांड्रिंग मामले में बड़े पैमाने पर छापेमारी की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई जेपी एसोसिएशन लिमिटेड, जेपी इंफ्राटेक और उनसे जुड़े अन्य कंपनियों व संस्थाओं के ठिकानों पर की जा रही है। कुल 15 परिसरों में तलाशी की जा रही है, जिनमें नोएडा के तीन प्रमुख बिल्डरों के ठिकाने भी शामिल हैं।



मनी लांड्रिंग के साक्ष्य मिले, कंप्यूटर रिकॉर्ड भी बरामद

सूत्रों के अनुसार अब तक की कार्रवाई में जांच एजेंसी को महत्वपूर्ण साक्ष्य हाथ लगे हैं, जिनसे साफ जाहिर होता है कि संबंधित कंपनियों मनी लांड्रिंग में लिप्त हैं। तलाशी के दौरान फाइलों के अलावा कंप्यूटरों से भी भारी मात्रा में रिकॉर्ड बरामद हुए हैं। निवेशकों के अतिरिक्त अन्य संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा धनराशि निवेश करने के दस्तावेज भी मिले हैं, जिनकी गहराई से जांच की जाएगी।

सबवेंशन स्कीम के नाम पर ठगी का मामला

यह कार्रवाई उन आरोपों से जुड़ी है जिसमें हजारों होम बायर्स को सबवेंशन स्कीम के तहत फ्लैट बेचे जाने का झांसा देकर ठगी की गई है। बिल्डरों ने खरीदारों को 10 फीसदी या तय राशि लेकर फ्लैट बुक किया, जिसमें दावा किया गया कि कच्चा मिलने तक किसी भी किस्त का भुगतान नहीं करना होगा।

बिल्डरों की चालाकी से खरीदार फंसे

फ्लैट बुकिंग के दौरान बिल्डर खरीदार के नाम पर बैंक से होम लोन भी करा लेते हैं। लेकिन कच्चा में देरी या आर्थिक तंगी के कारण बिल्डर ईएमआई भुगतान रोक देते हैं। चूंकि लोन खरीदार के नाम पर होता है, इसलिए बैंक ईएमआई के लिए खरीदार को परेशान करता है।

केंद्र सरकार एकीकृत पेंशन योजना लाने की दिशा में कर रही काम

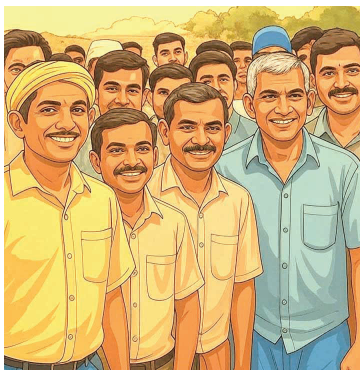
तोहफा

छह करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिकों को मिलेगा पेंशन

▶ पेंशन योजना में शामिल होने वाले श्रमिकों को अपनी जेब से नहीं देना होगा कोई अंशदान
▶ उपकर के तौर पर ली गई धनराशि का होगा इस्तेमाल

एजेंसी | नई दिल्ली

देशभर में विभिन्न तरह के निर्माण कार्यों में लगे करीब छह करोड़ श्रमिकों को सरकार बड़ी सीमागत देने की तैयारी में है। श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार नई एकीकृत पेंशन योजना लाने की दिशा में काम कर रही है। इसमें श्रमिकों को कोई अंशदान नहीं देना होगा। बल्कि निर्माण कार्यों पर लिए जाने वाले उपकर (सेस) की धनराशि का इस्तेमाल किया जाएगा।



प्रमुख राज्यों के कल्याण बोर्ड के पास उपलब्ध रकम

महाराष्ट्र	9,731.83 करोड़
कर्नाटक	7,547.23 करोड़
उत्तर प्रदेश	6,506.04 करोड़

यह योजना गिग वर्क की पेंशन योजना के ही समान होगी। सूत्रों का कहना है कि श्रम एवं जाएगी कि राज्य आसानी से जुड़कर अपने यहां काम कर रहे श्रमिकों की पेंशन में योगदान

लाभ राज्यों के माध्यम से श्रमिकों को मिलना है। इसलिए योजना में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि राज्य आसानी से जुड़कर अपने यहां काम कर रहे श्रमिकों की पेंशन में योगदान

कर पाएंगे। मुख्य तौर पर बिल्डिंग और अन्य तरह के निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को योजना का लाभ मिलेगा। इसलिए राज्यवार उनके पंजीकरण की व्यवस्था दी जाएगी।

राज्यों के पास पड़ा है रिजर्व फंड

राज्य सरकारों द्वारा निर्माण कार्य पर एक से दो प्रतिशत के बीच सेस यानी उपकर लिया जाता है। नियमों के तहत यह उपकर श्रमिकों से जुड़े कल्याण कार्यों की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। वर्ष 2005 के बाद से राज्य सरकारों ने 1.20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि राज्य सरकारों ने जुटाई। इसमें से 70700 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि राज्यों के श्रम कल्याण बोर्डों के पास पड़ी है, जिसका कोई सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। राज्यों के पास कोई दोस योजना नहीं केंद्र सरकार का मानना है कि राज्य सरकारों के पास रिजर्व फंड लगातार बढ़ रहा है।

श्रमिक संगठनों का भी खर्चों को लेकर रहा विरोध

बीते काफी वर्षों से श्रमिक संगठन आरोप लगाते आए हैं कि ज्यादातर राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम को लागू नहीं कर रहे हैं। निर्धारित लाभ में कटौती की जा रही है। राज्यों के श्रमिक कल्याण बोर्डों के पास पड़ी धनराशि को राज्य के खजाने में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है।

वैष्णवी आत्महत्या मामला

फरार ससुर और बेटा गिरफ्तार



7 दिन थे फरार

5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए आरोपी

वैष्णवी के पति, सास और ननद की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी

एजेंसी | पुणे

बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में फरार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता और उनके बेटे को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आज दोपहर दोनों को पुणे शिवाजीनगर अदालत में पेश किया गया। इस दौरान पुणे पुलिस ने मामले की जांच के लिए दोनों की हिरासत मांगी थी। अदालत ने पुलिस के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और 5 दिन की पुलिस हिरासत मंजूर कर ली। इसलिए राजेंद्र हगवणे और सुशील हगवणे अब 28 मई तक पुलिस हिरासत में रहेंगे।

केस डायरी

एनसीपी नेता राजेंद्र हगवणे की छोटी बहू वैष्णवी हगवणे ने सुसाइड कर लिया है, ऐसी जानकारी सामने आई थी। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह दावा किया गया कि वैष्णवी ने सुसाइड नहीं किया था उसकी हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम में वैष्णवी हगवणे के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। ये चोट के निशान पिटाई के बाद बने लग रहे हैं। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, वैसे ही राजेंद्र हगवणे और उनका बेटा सुशील फरार हो गए।

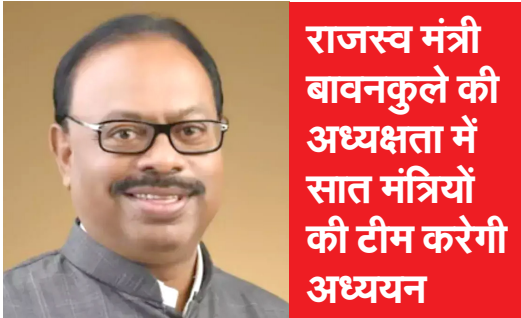
और भी लग सकती हैं धाराएं

सुनवाई के बाद वैष्णवी की ओर से दलीलें रख रहे वकीलों ने मीडिया को जवाब दिया। वकील ने बताया कि दो आरोपियों को लाया गया है। उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। आज पहली पीसी थी। जांच अभी बाकी है। सामान को जब्त करना बाकी है।

हत्या को बताया सुसाइड... ऐसे खुला राज!

एनसीपी नेता राजेंद्र हगवणे की छोटी बहू वैष्णवी हगवणे ने सुसाइड कर लिया है, ऐसी जानकारी सामने आई थी। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह दावा किया गया कि वैष्णवी ने सुसाइड नहीं किया था उसकी हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम में वैष्णवी हगवणे के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। ये चोट के निशान पिटाई के बाद बने लग रहे हैं। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, वैसे ही राजेंद्र हगवणे और उनका बेटा सुशील फरार हो गए।

पदभर्ती आरक्षण के लिए राज्य मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित



डीबीडी संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश के आठ आदिवासी बहुल जिलों में सरकारी नौकरियों के समूह 'सी' और 'डी' पदों के लिए आरक्षण का प्रतिशत और रोस्टर (बिंदुनामावली) तय करने हेतु एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया है। इस उपसमिति की अध्यक्षता राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले करेंगे।

इन जिलों के लिए तय होंगे आरक्षण मानक

उपसमिति पालघर, नाशिक, नंदूरबार, धुलिया, यवतमाल, गडचिरोली, रायगढ़ और चंद्रपुर जिलों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), विमुक्त जाति, घुमंतु जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए लागू आरक्षण की समीक्षा करेगी।

अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार

डीबीडी संवाददाता । भिवंडी

भिवंडी क्राइम ब्रांच ने बांग्लादेश की एक महिला सुमी कमाल शेख (31 वर्ष) को भारत में अवैध रूप से प्रवेश और निवास के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी 22 मई 2025 को दोपहर 4:05 बजे की गई और उसी रात 9:34 बजे महिला को भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला बांग्लादेश के जिला जिहोदा के ग्राम बोनगिरा की रहने वाली है। उसने बिना किसी वैध पासपोर्ट या वीजा के भारत-बांग्लादेश सीमा पार की और भिवंडी के हनुमान टेकडी इलाके में एक चॉल के रूम नं. 01 में छिपकर रह रही थी। इस मामले में महिला पुलिस हवलदार माया डोंगरे ने



शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी के खिलाफ पारपत्र अधिनियम 1920 की धारा 3 और 4, तथा परकीय नागरिक अधिनियम 1946 की धारा 13 व 14(अ) के तहत मामला दर्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध विदेशी महिला इलाके में रह रही है, जिसके आधार पर जांच की गई और उक्त महिला को हिरासत में लिया गया। भिवंडी पुलिस अब यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महिला भारत में किन गतिविधियों में शामिल थी, और क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा है।

मानसून से पहले भिवंडी मनपा का सख्त कदम 21 अतिथोकादायक इमारतें कराई गई खाली



डीबीडी संवाददाता । भिवंडी

मानसून के मद्देनजर भिवंडी महानगरपालिका ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शहर की 21 अतिथोकादायक इमारतों को खाली कराने का अभियान तेज कर दिया है। 1 मई से 20 मई 2025 तक विभिन्न प्रभागों में ये कार्रवाई की

गई है, जिसमें प्रभाग 1 में 1, प्रभाग 3 में 5, प्रभाग 4 में 12 और प्रभाग 5 में 3 इमारतें शामिल हैं। मनपा ने कुल 104 इमारतों को थोकादायक या अतिथोकादायक घोषित कर उनके पानी और बिजली के कनेक्शन काट दिए हैं। इन इमारतों को जल्द से जल्द खाली कराने की प्रक्रिया भी जारी है।

इन मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी

उपसमिति में सात कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिनमें सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उर्डेके, अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, कृषि मंत्री माणिकराव कोकटे, स्कूली शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे, और खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल शामिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को उपसमिति का सदस्य सचिव बनाया गया है, जबकि विधि व न्याय विभाग के सचिव विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

एक माह में देनी होगी रिपोर्ट

उपसमिति को इन आठ जिलों में समूह 'सी' और 'डी' के पदों के लिए आरक्षण का नया प्रारूप तय कर, एक महीने के भीतर राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने होगी।

कोर्ट ने हत्यारोपी को किया बरी

गवाहों के बयानों में विरोधाभास और साक्ष्यों के अभाव से नहीं सिद्ध हो सका आरोप

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2018 में हुए हत्या के मामले में गवाहों के बयानों में विरोधाभास और ठोस साक्ष्यों के अभाव को देखते हुए 45 वर्षीय परमेश्वर उर्फ प्रमोद सुदमराज पाटेकर को बरी कर दिया है। यह आदेश न्यायाधीश एस.बी. अग्रवाल ने 15 मई को दिया, जिसकी प्रति शुक्रवार को उपलब्ध

इयूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस और वार्डन से मारपीट

डीबीडी संवाददाता । भिवंडी

शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम को नियंत्रण में रखने के लिए तैनात ट्रैफिक पुलिस और वार्डन के साथ तीन लोगों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, शनिवार दोपहर करीब तीन बजे शहर यातायात शाखा के पुलिस कर्मी काशीनाथ ईश्वर राठौड़ रहनाल गांव सीमा पर ट्रैफिक नियंत्रित



कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मुशरफ जुबैर अंसारी (25), साहिल मोहम्मद कमर बिश्ती (31) और जैद जुबैर अंसारी (20) की गाड़ी रोक ली। आरोपियों ने पहले वार्डन से बहस शुरू की और फिर पुलिसकर्मी राठौड़ के साथ भी विवाद कर उनकी सरकारी वर्दी को नुकसान पहुंचाया।

तीन आरोपी गिरफ्तार

तीनों आरोपियों ने पुलिसकर्मी को धमकाया, गाली-गलौज की और सरकारी कामकाज में बाधा डाली। इस पर नारपोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा है कि ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।



कराई गई। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि पाटेकर ने 24 मई 2018 को ठाणे के वागले एस्टेट इलाके में शराब को लेकर विवाद के बाद सिद्धार्थ प्रकाश चंदमारे पर चाकू से हमला किया था।

बयानों में मिले विरोधाभास

अदालत ने पाया कि मुख्य गवाह प्रवीण वाघमारे के बयानों में प्राथमिकी और अदालत में विरोधाभास था। घटना स्थल पर केवल प्रवीण मौजूद था, जबकि कोई अन्य चरमदीद गवाह नहीं था। अभियोजन के अन्य गवाह आशा कांबले और मृतक की बहन नीलम चंदमारे को भी अदालत ने भरोसेमंद नहीं माना।

साक्ष्यों में मिली अनियमितताएं

अदालत ने हत्या में इस्तेमाल चाकू की बरामदगी में कई अनियमितताओं को भी रेखांकित किया। आरोपी के घायों की कोई मेडिकल जांच भी नहीं कराई गई थी। न्यायाधीश ने कहा, 'गवाहों के बयानों में कई बड़े विरोधाभास हैं और अभियोजन पक्ष आरोपी की दोषसिद्धि को पूरी तरह साबित करने में नाकाम रहा।' इस कारण अदालत ने आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

मंत्री विजय शाह के बेतुके बयान पर भिवंडी कोर्ट में शिकायत

कांग्रेस ने की बर्खास्तगी की मांग

डीबीडी संवाददाता । भिवंडी

मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित और बेतुके बयान को लेकर अब मामला अदालत तक पहुंच गया है। कांग्रेस की प्रदेश महासचिव रानी अग्रवाल ने भिवंडी कोर्ट में उनके खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। रानी अग्रवाल ने भाजपा नेतृत्व से विजय शाह को मंत्री पद से तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कश्मीर के लिए मनपा की यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर मनपा का यह कदम शहरवासियों के लिए राहत का संकेत है।



गई थी। लेकिन इस पर मंत्री विजय शाह ने इस्लाम और मुस्लिम महिलाओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की, जिसे लेकर देशभर में नाराजगी देखी गई है। रानी अग्रवाल ने बताया कि मंत्री विजय शाह के बयान पर कोर्ट ने गंभीर संज्ञान लिया है और भारतीय सेना की महिला अधिकारी के अपमान को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए फटकार लगाई है। उन्होंने मांग की है

कि आईपीसी की धारा 196 और 197 के तहत विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कांग्रेस महासचिव ने भाजपा नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे देश में आलोचना के बावजूद अब तक पार्टी ने मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। यह सीधे तौर पर सेना के सम्मान और देश के संविधान की गरिमा का उल्लंघन है।

7.64 करोड़ का बैंक धोखाधड़ी

फर्जी दस्तावेजों से खोले 75 से अधिक खाते

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

ठाणे शहर में जालसाजों ने एक व्यक्ति के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर कई बैंकों में फर्जी खाते खोले हुए 7.64 करोड़ रुपए का धनशोधन किया। पुलिस ने शुक्रवार को इस बड़े घोटाले का खुलासा करते हुए बताया कि मामले में वागले एस्टेट पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता और अन्य लोगों को चालू खाते खुलवाने के बदले प्रति खाता 5,000 रुपए देने का झांसा दिया था। आरोपी ने बैंध व्यवसाय का दिखावा करते हुए भरोसा दिलाया कि इन खातों का उपयोग केवल धन हस्तांतरण के लिए होगा।



फर्जी कंपनियों की आड़ में चल रहा था खेल

बाद में पीड़ित को पता चला कि इन खातों का उपयोग फर्जी कंपनियों की आड़ में अवैध लेन-देन और धनशोधन के लिए किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अक्टूबर 2023 से मई 2025 के बीच कुल 75 से अधिक फर्जी बैंक खातों के जरिए 7.64 करोड़ रुपए का अवैध लेन-देन किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 61(2) (अपराधिक साजिश), 316(2) (अपराधिक विश्वासघात), 318(4) (धोखाधड़ी) और अन्य प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज किया है। हालांकि, अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और जांच जारी है।

'चेन्नई पैटर्न' के खिलाफ ठाकरे गुट का एल्गार

सड़कों पर उतरने की चेतावनी

डीबीडी संवाददाता । डोंबिवली

कल्याण-डोंबिवली मनपा (K.D.M.C.) में लागू किए गए 'चेन्नई पैटर्न' कचरा संकलन योजना के खिलाफ शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। पार्टी की ओर से जिला प्रमुख दिपेश म्हात्रे के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे जनता से लुट और मनपा की भ्रष्ट नीतियों का प्रतीक बताया गया। दिपेश म्हात्रे ने कहा कि इस नई कर व्यवस्था में नागरिकों पर 600 की बजाय 900 रुपए सालाना कचरा कर थोपा गया है। यह कर सभी पर समान रूप से लगाया गया है, भले ही मकान छोटा हो या बड़ा। उन्होंने कहा कि यह सीधा आर्थिक शोषण है, जिसे जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। शिवसेना नेताओं का आरोप है कि इस योजना

900 रुपए वार्षिक कर को बताया जनविरोधी



में केवल कचरा इकट्ठा किया जाएगा, कुल क्षमता सिर्फ 650 टन की है। लेकिन उसका प्रसंस्करण नहीं होगा। शहर में रोजाना 850 टन कचरा निकलता है, लेकिन तीन संयंत्रों की

शहर की बदहाल हालत पर उठाए सवाल

उन्होंने बताया कि नालियों की सफाई नहीं हो रही, कंक्रीट सड़कें अघूरी हैं, सीवर लाइनें जाम हैं और मानसून से पहले जरूरी काम टप पड़े हैं। नए ठेकेदारों की नियुक्ति नहीं हुई और प्रशासन निष्क्रिय है। शिवसेना (ठाकरे गुट) ने चेताया कि यदि प्रशासन ने टैक्स वापसी और बुनियादी सुविधाओं पर काम चरु नही किया, तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। साथ ही, आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे बड़े हुए कर का विरोध करें और अपने नागरिक अधिकारों के लिए खड़े हों।

धुलिया गेस्ट हाउस कैश कांड की जांच कमेटी पर हमें भरोसा नहीं: अनिल गोटे

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

सरकारी गेस्ट हाउस से मिले 1.84 करोड़ रुपए नकद के मामले में गठित विशेष जांच टीम (SIT) की निष्पक्षता पर शिवसेना (उद्धव) के नेता एवं पूर्व विधायक अनिल गोटे ने गंभीर सवाल उठाए हैं। गोटे ने कहा कि SIT जांच केवल दिखावा है और इसमें उन्हें राज्य सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। गोटे ने शुक्रवार को प्रेस से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भले ही SIT जांच के आदेश दिए हों, लेकिन इससे पहले जयकुमार रावल बैंक घोटाला और अब्दुल करीम तेलंगी मामले में भी SIT बनी थी, लेकिन बाद में वह जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी।



उन्होंने कहा, 'SIT और धुलिया पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है।' गोटे ने राज्य सरकार से मांग की कि इस मामले की जांच वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रवीण गेडाम, तुकाराम मुंडे और धुलिया के पूर्व कलेक्टर राहुल रेखावार की निगरानी में स्वतंत्र कमेटी द्वारा की जाए। उन्होंने कहा कि तभी जनता के सामने सच्चाई आ पाएगी।

'5 करोड़ की रिश्वत के लिए जमा की गई थी राशि'

अनिल गोटे ने खुलासा किया कि यह रकम ठेकेदारों द्वारा विधानमंडल की आकलन समिति को घूस देने के लिए जमा की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस भ्रष्टाचार की पोल खोली तो उसके बाद राज्य सरकार ने आनन-फानन में SIT जांच के आदेश दिए, लेकिन यह सिर्फ दिखावे के लिए है। गोटे ने दो टुक कहा, 'SIT जांच समय की बर्बादी है। सरकार अगर वास्तव में इस मामले की पारदर्शी जांच चाहती है, तो उसे स्वतंत्र और ईमानदार अफसरों की कमेटी से जांच करानी चाहिए।'

गिग श्रमिकों के लिए नया कानून बनाने की योजना

► ई-कॉमर्स डिलीवरी बॉय समेत सभी गिग श्रमिकों को मिलेगा कानूनी संरक्षण

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले गिग श्रमिकों के लिए जल्द ही एक विशेष कानून बनाया जाएगा। राज्य के श्रम विभाग के अधिकारी ने बताया कि ई-कॉमर्स कंपनियों में अनुबंध पर काम करने वाले डिलीवरी बॉय और अन्य गिग श्रमिकों के कल्याण, नियमन और सामाजिक सुरक्षा के लिए यह कानून तैयार किया जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा कानून

अधिकारी ने कहा कि नए कानून के लागू होने से गिग श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के मानक लागू होंगे। इसके तहत



कानून का प्रारूप तैयार, अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन कर्नाटक, राजस्थान और झारखंड में पहले से लागू गिग श्रमिक कानूनों के आधार पर महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कानून बनेगा। इसके लिए ई-कॉमर्स कंपनियों, गिग श्रमिकों के संगठन और एग्रीगेटरों से राय ली जाएगी। कानून के प्रारूप को अंतिम रूप देने के बाद इसे राज्य मंत्रिमंडल में पेश किया जाएगा।

गिग श्रमिकों का बेहतर नियमन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए फंडिंग व्यवस्था का भी प्रावधान किया जाएगा।

ई-श्रम पोर्टल पर गिग श्रमिकों का पंजीकरण जारी

राज्य में गिग श्रमिकों की संख्या का सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन लगभग 8 लाख गिग श्रमिक काम कर रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार के असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बनाए गए ई-श्रम पोर्टल पर गिग

श्रमिकों का पंजीकरण चल रहा है। अभी तक करीब 45 हजार गिग श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। यह पंजीकरण राज्य के श्रम आयुक्त और विकास आयुक्त के माध्यम से एग्रीगेटरों की मदद से हो रहा है।

प्रमुख ऑनलाइन कंपनियों की मौजूदगी

महाराष्ट्र में 321 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनियां पंजीकृत हैं, जिनमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, मेक माय ट्रिप, स्विगी, जोमेटो जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। इन कंपनियों का सालाना टर्नओवर लगभग 45 हजार करोड़ रुपये है और यहां लगभग 2 लाख नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं।

माता रमाबाई अंबेडकर नगर पुनर्विकास परियोजना

दीपक पवार । मुंबई

मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने घाटकोपर स्थित माता रमाबाई अंबेडकर नगर और कामराज नगर पुनर्विकास परियोजना के पहले चरण की निविदा प्रक्रिया शनिवार, 23 मई को शुरू कर दी है। इस चरण में कुल 6 पुनर्बासित 22 मंजिला इमारतों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें 4053 घर होंगे। इन घरों की कुल निर्माण लागत लगभग 1450 करोड़ रुपये होगी।



6 इमारतों के निर्माण के लिए निविदा जारी

पहले चरण में 4053 मकानों का होगा निर्माण, लागत 1450 करोड़ रुपए

पुनर्विकास की प्रमुख बातें

हर इमारत में दो विंग, और प्रत्येक मंजिल पर 32 घर होंगे। हर घर का आकार 300 वर्ग फीट होगा। निर्माण कार्य 17 एकड़ भूमि पर किया जाएगा, जो पहले ही साफ कर दी गई है। परियोजना के तहत कुल 14,000 झुग्गियों का पुनर्विकास किया जाना है। इनमें से 1,694 घर पूर्वी एक्सप्रेसवे विस्तार के कारण सीधे प्रभावित हैं।

मुंबई सेंट्रल-राजकोट और मुंबई सेंट्रल-गांधीधाम के बीच चलेगी सुपरफास्ट तेजस स्पेशल ट्रेनें

पश्चिम रेलवे द्वारा दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा विशेष रूप से ग्रीष्मकाल के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के लिए मुंबई सेंट्रल और राजकोट तथा मुंबई सेंट्रल और गांधीधाम के बीच विशेष किराये पर सुपरफास्ट तेजस स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा विशेष किराए पर दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे भी विस्तारित किये गये हैं।

स्पेशल ट्रेनों का विवरण

मुंबई सेंट्रल - राजकोट तेजस सुपरफास्ट द्वि-साप्ताहिक स्पेशल

ट्रेन संख्या 09005 मुंबई सेंट्रल-राजकोट स्पेशल हर बुधवार और शुक्रवार को मुंबई सेंट्रल से 23.20 बजे रवाना होगी और अगले दिन 11.45 बजे राजकोट पहुंचेगी। यह ट्रेन 30 मई से 27 जून, 2025 तक चलेगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09006 राजकोट-मुंबई सेंट्रल स्पेशल हर गुरुवार और शनिवार को राजकोट से 18.30 बजे रवाना होगी और अगले दिन 07.30 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन 31 मई से 28 जून, 2025 तक चलेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद, विरमगाम, सुरेंद्रनगर और वानकानेर स्टेशनों पर रुकेगी।



और अगले दिन 12.55 बजे गांधीधाम पहुंचेगी। यह ट्रेन 02 जून से 30 जून, 2025 तक चलेगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09018 गांधीधाम-मुंबई सेंट्रल स्पेशल प्रत्येक मंगलवार को गांधीधाम से 18.55 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 07.30 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन 03 जून, 2025 से 01 जुलाई, 2025 तक चलेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद, विरमगाम, सामाख्यली और भचाऊ स्टेशनों पर रुकेगी।

विस्तारित होने वाली ट्रेनें: ट्रेन संख्या 09067 उधना-जयनगर अनारक्षित स्पेशल को 29 जून, 2025 तक विस्तारित किया गया है। ट्रेन संख्या 09068 जयनगर-उधना अनारक्षित स्पेशल को 30 जून, 2025 तक विस्तारित किया गया है। ट्रेन संख्या 09069 उधना-समस्तीपुर स्पेशल को 28 जून, 2025 तक विस्तारित किया गया है। ट्रेन संख्या 09070 समस्तीपुर-उधना स्पेशल को 30 जून, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

मुंबई सेंट्रल-गांधीधाम तेजस सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल

ट्रेन संख्या 09017 मुंबई सेंट्रल-गांधीधाम स्पेशल प्रत्येक सोमवार को मुंबई सेंट्रल से 23.20 बजे प्रस्थान करेगी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीमा शुल्क विभाग को दिया झटका

► जब सोने के रिफंड विवाद में आदेश रद्द, नई सुनवाई का निर्देश

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीमा शुल्क विभाग के कस्टम्स ऑर्डर को रद्द कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता को जब्त सोने के 41 लाख रुपए की बजाय केवल डेढ़ लाख रुपए का रिफंड दिया गया था। न्यायमूर्ति बी.पी. कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की पीठ ने मामले की नई सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया है।



याचिका में जब्त सोने की बिक्री पर विवाद

याचिका में आरोप लगाया गया कि सीमा शुल्क विभाग ने याचिकाकर्ता के जब्त सोने को बिना सूचना दिए बेच दिया। याचिकाकर्ता शब्बीर अहमद कुरेशी ने 41 लाख 47 हजार रुपए के रिफंड का

दावा किया था, लेकिन विभाग ने केवल 1 लाख 50 हजार रुपए रिफंड किए। इससे पहले सीमा शुल्क न्यायाधिकरण ने 19 लाख 69 हजार रुपए रिफंड करने का आदेश दिया था।

पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए दलील

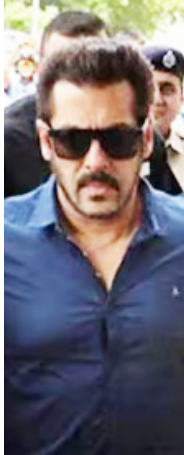
याचिकाकर्ता के वकील प्रकाश शिंगरानी ने 'लेयला महमूदी बनाम अतिरिक्त सीमा शुल्क आयुक्त' मामले का उल्लेख किया, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि बिना उचित सूचना के जब्त किए गए सोने के आभूषणों का एकतरफा निपटान अधिकारों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि विभाग ने उन्हें जवाब देने का मौका नहीं दिया।

सूचना की वैधता पर सवाल

याचिकाकर्ता ने सोने की बिक्री से संबंधित कोई नोटिस प्राप्त करने से इनकार किया, जबकि सीमा शुल्क ने फरवरी 2019 और 2020 में नोटिस जारी करने का दावा किया। अदालत ने नोटिसों के लिए कोई पावती या आधिकारिक आदेश नहीं पाए जाने पर सवाल उठाए।

सलमान की सुरक्षा बढ़ी

गैलेक्सी अपार्टमेंट में पहचान के बाद मिलेगा प्रवेश



मुंबई। अभिनेता सलमान खान की गैलेक्सी अपार्टमेंट में हाल ही में दो अनजान व्यक्तियों के प्रवेश के मामले सामने आने के बाद मुंबई पुलिस सतर्क हो गई है। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है, जिसके तहत अब किसी भी व्यक्ति को अपार्टमेंट में प्रवेश देने से पहले वहां रहने वाले निवासियों से उसकी पहचान की पुष्टि कराई जाएगी।

नई सुरक्षा व्यवस्था जल्द लागू करने की तैयारी

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह व्यवस्था जल्द लागू की जाएगी ताकि गैलेक्सी अपार्टमेंट में अनजान लोगों के प्रवेश को रोका जा सके। इससे सलमान खान और अन्य निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

मॉडल ने बजाई थी डोर बेल

20 और 21 मई को सलमान की इमारत में दो लोग घुस गए थे, जिनमें से एक महिला मॉडल ईशा खबरा थी। वह लिफ्ट में सलमान के घर की लॉबी तक पहुंची और वहां डोर बेल भी बजाई थी। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ी पहल शुरू की गई है।

RfX (Tender) No.		Name of work	Estimated cost in Rs.	EMD (Rs.)	Tender fee incl. GST (Rs.)
7000036235		2nd Call for Engaging Skilled / Semi Skilled/ Unskilled Manpower on Outsourcing Basis for HVDC RS (O&M) Circle, Padghe.	INR 93,41,198/- (including taxes)	INR 93,411.98/-	INR 590/-
1	Date of download of RfX (e tender) documents		From- 24.05.2025 from 00.00 hrs. to 03.06.2025 up to 10.00 hrs.		
2	Date of submission of RfX (e tender)		03.06.2025 up to 10.00 hrs.		
3	Date of technical bid opening		03.06.2025 up to 11.00 hrs. (If possible)		
4	Date of commercial bid opening		03.06.2025 up to 13.00 hrs. (If possible)		
Contact Person: THE MANAGER (HR), HVDC RS (O&M) Circle, Padghe, Mob. No: 9833071793					
For further details visit our website: https://srmetender.mahatransco.in					
Sd/- Superintending Engineer, HVDC RS O&M Circle, Padghe					

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन निविदा के लिए सूचना

विषय: भूस्खलन आपदा समूह ए से समूह बी के लिए मॉनसून अवधि के दौरान ग्रेटर मुंबई के पूर्वी उपनगरों में तैनात एन.डी.आर.एफ. टीम के उपयोग के लिए किराए के आधार पर 1 बस (35 सीटिंग क्षमता) की तैनाती।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का परिवहन विभाग, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) "भूस्खलन आपदा समूह ए से समूह बी के लिए मॉनसून अवधि के दौरान ग्रेटर मुंबई के पूर्वी उपनगरों में तैनात एन.डी.आर.एफ. टीम के उपयोग के लिए किराए के आधार पर 1 बस (35 सीटिंग क्षमता) की तैनाती" के कार्य के लिए योग्य निविदाकर्ता से निविदा दस्तावेज में उल्लिखित अनिवार्य पूर्व-योग्यता मानदंडों के अनुसार ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित करता है।

बोली संख्या 2025-mcGm_1183422 और 2025_MCGM-1183459

बोली आरंभ तिथि और समय 24.05.2025 को 11:00 बजे के बाद है।

बोली समाप्ति तिथि और समय 29.05.2025 को 04:00 बजे तक है।

बोलियां महाराष्ट्र सरकार के पोर्टल (महाटेंडर्स) (<http://mahatenders.gov.in>) के ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम से डाउनलोड की जा सकती हैं। साथ ही निविदा की प्रति BMC के पोर्टल <http://portal.mcgm.gov.in> से "ई-प्रोक्योरमेंट" अनुभाग के अंतर्गत डाउनलोड की जा सकती है।

कृपया ध्यान दें कि बोली दस्तावेज डाक द्वारा जारी या प्राप्त नहीं किया जाएगा। अब से, इस निविदा के बारे में सभी शुल्क, नोटिस, अपडेट, संशोधन, शुद्धिपत्र, आगे के विवरण आदि केवल महाटेंडर पोर्टल पर पोस्ट किए जाएंगे।

हस्ता/- पीआरओ/ 505/विज्ञा./2025-26	उप मुख्य अभियंता (एसडब्ल्यूएम) परिवहन
समय पर उपचार, बचाए प्राण।	

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

ACME/587/जनरल/AEM-II दिनांक 22.05.2025

ई-स्पाट कोटेशन नोटिस

विभाग	सहायक अभियंता (मैटेन-II) "एम/ईस्ट" वार्ड
विषय	बकरीद के दौरान पे एंड पार्क सुविधा का संचालन - सायन पनवेल हाईवे पर 202 ऑक्ट्रॉय नाका, एम/ईस्ट वार्ड 400043
निविदा दस्तावेज प्राप्त करने की आरंभ तिथि और समय	23/05/2025 प्रातः 10.30 बजे
निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि और समय	27/05/2025 प्रातः 11.00 बजे
कोटेशन खुलने की तिथि	27/05/2023 प्रातः 11.30 बजे
ईएमडी राशि	₹ 23,600.00/-
अनुबंध की समय अवधि	27.05.2025 से 10.06.2025
कोटेशन फॉर्म शुल्क/जांच शुल्क	₹. 429/-सीजीएसटी और एसजीएसटी सहित
वेबसाइट	http://portal.mcgm.gov.in
संपर्क अधिकारी का नाम और नंबर	श्री संतोष मेथर, सहायक अभियंता (मैटेन-I) एम/ईस्ट वार्ड मोबाइल नंबर 9619081122 श्री. सचिन पाटिल, एस.ई. (मैटेनेंस) मोबाइल नं.9702352107
ईमेल आईडी	aemaint01.meast@mcgm.gov.in

sd/-22.05.2025 पीआरओ/ 502/विज्ञा./2025-26	वार्ड कार्यकारी अभियंता (मैटेनेंस) 'एम/ईस्ट'
समय पर उपचार, बचाए प्राण।	

न्यूज़ ब्रीफ

यूपी पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग फेरबदल का क्रम जारी है। शुक्रवार को भी बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। नवीनतम जारी आदेशों में 27 उपाधीक्षकों का तबादला किया गया है। इससे एक पहले गुरुवार को 25 पीपीएस अधिकारियों को तबादला किया गया था।

रेलवे ने आजाद नगर में तोड़े अवैध निर्माण

प्रयागराज। दिल्ली-हावड़ा रेलखंड पर प्रयागराज से पीडीडीयू के बीच तीसरी लाइन बिछाने के लिए रेलवे की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटया जाने लगा है। गुरुवार को रेलवे ने साउथ मलाका के आजाद नगर में बैकहो लोडर (जेसीबी) से ट्रैक किनारे बने छह अवैध निर्माण को ध्वस्त कर कराया। इस कार्रवाई से मोहल्ले में खलबली मच गई और स्थानीय लोग अपने सामान समेटने में जुट रहे।

सिपाही का संदिग्ध हालात में मिला शव

उन्नाव। माखी क्षेत्र में रसूलाबाद माखी रऊ मार्ग पर एक खाली पड़े मकान के पास खेत में बहराइच जिले में तैनात सिपाही का शव संदिग्ध हालात में शुक्रवार सुबह पड़ा मिला। दिवंगत का चेहरा खून से सना था, पेट पर खरोंच के निशान मिले हैं और पीठ काली पड़ी थी। स्वजन के अनुसार सिपाही 17 मई को बहराइच से डाक लेकर लखनऊ आया था। वहां से घर आ गया था। गुरुवार को गांव के किसी साथी के साथ कानपुर दवा लेने गया था। वहा से लौटने के बाद पिता से फोन पर बात की थी। लेकिन रात में घर नहीं पहुंचा। पुलिस मुंह के बल गिरने से आई चोट और अधिक रक्त स्राव के कारण मौत होना मान रही है। स्वजन ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है जो रात सिपाही के साथ देखे गए हैं।

बच्चे की दिनदहाड़े गला रेतकर हत्या

चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जुगीदारू गांव के बांधाटोला में आपसी रंजिश में 12 वर्षीय बच्चे की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गयी। मृतक अर्जुन बानसिंह जुगीदारू गांव निवासी सिकुर बानसिंह का बेटा था। घटना गुरुवार दिन के करीब 3 बजे की बताया जा रही है। देर शाम घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस गांव पहुंची और घटना स्थल से शव उठाकर सदर अस्पताल लायी। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी चंद्रमोहन बानसिंह को गिरफ्तार का लिया है।

फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर ठगी, तीन गिरफ्तार

पटना। खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर लोगों से ठगी और मौका मिलने पर पिस्टल दिखाकर लूटपाट करने वाले गिरोह के तीन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरोह पुलिस के निशाने पर तब आया, जब हाल ही में इसके पुरी थाना क्षेत्र में एक युवक से पिस्टल दिखाकर लूटपाट की घटना सामने आई। इसके पुरी थाने की पुलिस ने इनके पास से दो बाइक बरामद की है, जिस पर पुलिस का स्ट्रीकर लगा हुआ है। दो पिस्टल, एक कट्टा, सेना की वर्दी नेम प्लेट सहित, सीबीआई का नकली परिचय पत्र और ब्लैक चेक भी बरामद किया गया है।

एशिया के सबसे पुराने रेल कारखाने का होगा कायाकल्प

एजेंसी | पटना

देश और एशिया के सबसे पुराने जमालपुर रेल कारखाने ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक पल देखा, जब 17 साल बाद कोई रेल मंत्री वहां पहुंचे। इससे पहले लालू यादव वहां जाकर निरीक्षण किए थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव विशेष ट्रेन से पटना से रवाना होकर जैसे ही जमालपुर स्टेशन पहुंचे, स्टेशन परिसर में ढोल-नगाड़ों और भारत माता की जय के नारों से उनका जोरदार स्वागत हुआ। उनके स्वागत के लिए स्थानीय नेता, कार्यकर्ता और आम लोग सुबह से ही स्टेशन पर जुटे थे।



17 साल बाद पहुंचा कोई रेल मंत्री

अत्याधुनिक वैगन पीओएच स्थल की आधारशिला भी रखी

इस मौके पर रेल मंत्री ने 78 १96 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक वैगन पीओएच (Periodical Overhauling) स्थल की आधारशिला भी रखी। इस केंद्र के बनने से जमालपुर कारखाने की क्षमता में बड़ा इजाफा होगा और हर महीने 545 से 800 वैगनों की मरम्मत की जा सकेगी। यह रेलवे के मालवाहन ढांचे को और मजबूत करेगा।

रामनयन पटेल होंगे अपना दल (एस) के राष्ट्रीय महासचिव

लखनऊ : अपना दल (एस) ने संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के निर्देश पर अवध नरेश वर्मा को राष्ट्रीय महासचिव के पद से कार्यमुक्त कर दिया गया है। उन्हें अब पार्टी की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके स्थान पर बस्ती जिले के रामनयन पटेल को राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व सौंपा गया है। यह निर्णय पार्टी के भविष्य के रणनीतिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर लिया गया है। अवध नरेश वर्मा ने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय महासचिव के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी संगठनात्मक क्षमता और समर्पण ने पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की। अब सलाहकार समिति में उनकी भूमिका से



पार्टी को उनके अनुभव और मार्गदर्शन का लाभ मिलेगा। पार्टी नेतृत्व ने उनके योगदान की सराहना करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। रामनयन पटेल को राष्ट्रीय महासचिव के रूप में नियुक्त किया जाना पार्टी के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है।

पटना में जल्द चलेगी वाटर मेट्रो गंगा नदी में दौड़ेगी लेटेस्ट इलेक्ट्रिक बोट, सर्वे का काम पूरा

एजेंसी | पटना

पटना में गंगा नदी में वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी हो रही है। वाटर मेट्रो नदी में चलने वाली एक तरह की इलेक्ट्रिक बोट होगी। इसमें यात्रियों को सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत पटना में गंगा नदी के किनारे आधुनिक वाटर मेट्रो स्टेशन बनेंगे। एनआईटी स्टेशन पर पटना मेट्रो को जोड़ा जायेगा। केरल से कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के अधिकारी पिछले दिनों पटना आए थे। उन्होंने गंगा और गंडक नदी में वाटर मेट्रो के लिए सर्वे किया। टीम ने पटना के दानापुर, दीधा, बिदुपुर, गायघाट और साथ ही सोनपुर व हाजीपुर में भी स्थल निरीक्षण किया। इन इलाकों में वाटर मेट्रो स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे और यात्री यहां से आसानी से बोट में चढ़ और उतर सकेंगे। साथ ही, एनआईटी घाट पर पटना मेट्रो को इस सेवा से जोड़ा जाएगा जिससे जल और मेट्रो परिवहन के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो सकेगा।

सीधा संपर्क होगा स्थापित

केरल के कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड की एक विशेषज्ञ टीम ने हाल ही में पटना का दौरा किया और गंगा एवं गंडक नदियों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने को लेकर संभावनाओं का सर्वेक्षण किया। इस दौरान टीम ने पटना के प्रमुख इलाकों जैसे दानापुर, दीधा, बिदुपुर, गायघाट और साथ ही सोनपुर व हाजीपुर में भी स्थल निरीक्षण किया। इन इलाकों में वाटर मेट्रो स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे और यात्री यहां से आसानी से बोट में चढ़ और उतर सकेंगे। साथ ही, एनआईटी घाट पर पटना मेट्रो को इस सेवा से जोड़ा जाएगा जिससे जल और मेट्रो परिवहन के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो सकेगा।

ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति

इस सेवा में इस्तेमाल होने वाली बोटें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होंगी, जिससे प्रदूषण मुक्त परिवहन सुनिश्चित होगा। एक बोट में लगभग 100 यात्रियों के बैठने और खड़े होकर सफर करने की व्यवस्था होगी, जिससे अधिक संख्या में लोगों को एक साथ यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। वाटर मेट्रो परियोजना के शुरू होने से पटना में ट्रैफिक जाम की समस्या में काफी कमी आने की उम्मीद है, साथ ही यह राज्य के पर्यटन क्षेत्र को भी एक नया आयाम दे सकती है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो आने वाले कुछ वर्षों में गंगा नदी पर यह परियोजना एक नया परिवहन मॉडल पेश करेगी।

कटिहार की मिट्टी से बंगाल में बन रहे मकान

►► बिहार के बदले बंगाल में भरा जा रहा टैक्स

एजेंसी | कटिहार

बिहार की चोरी की गई मिट्टी से बंगाल में भवन मकान बन रहे हैं। कटिहार व पश्चिम बंगाल के बार्डर पर ईंट कारोबारी बिहार के क्षेत्र में मिट्टी का अवैध खनन कर बंगाल पहुंचाया जा रहा हैं। मतलब बिहार में राजस्व की चोरी हो रही और बंगाल में टैक्स वसूला जा रहा है। बताया जाता हैं कि बिहार-बंगाल बार्डर के समीप अवैध रूप से मिट्टी खनन का कारोबार काफी तेजी से फल-फूल रहा है। कटिहार की मिट्टी का अवैध खनन कर पश्चिम बंगाल की ईंट भट्टों में अधिक दर पर भेजा जा रहा है।इस संबंध में पत्रकारों से बात करते हुए जिला खनन पदाधिकारी आकांक्षा प्रियदर्शी कहा कि अगर अवैध रूप से मिट्टी खनन हो रहा हैं, तो कार्रवाई कर जुमाना वसूला जाएगा। अवैध मिट्टी खनन पर अभियान चलाकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

चेकपोस्ट के रास्ते दिन में भी जा रही है मिट्टी



बंगाल से सटे प्राणपुर व रोशना थाना क्षेत्र से बड़े पैमाने पर रात के अंधेरे में एक्सकेवटर से मिट्टी का खनन कर हाइवा, ट्रक व ट्रैक्टर से सीमा पर कराकर इसे बंगाल तक भेजा जा रहा हैं। महानंदा नदी किनारे सरकारी जमीन से बिना खनन विभाग की अनुमति के मिट्टी का खनन किया जा रहा है। खनन माफियाओं पर नकेल कसने में खनन विभाग, स्थानीय पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन भी सफल नहीं हो रहा हैं। लाभ के समीप चेकपोस्ट भी हैं। दिन हो या रात चेकपोस्ट होकर मिट्टी लदे वाहन आसानी से पार हो रहे हैं। बताया जाता हैं कि पूर्व में सिर्फ ट्रैक्टर से चोरी छुपे मिट्टी की चोरी की जाती है, अब रात-दिन ट्रैक्टर समेत ट्राली, ट्रक से मिट्टी बिहार से बंगाल पहुंचाई जा रही है। अमदाबाद, प्राणपुर, रोशना, आजमनगर, बलरामपुर आदि प्रखंड में बड़े पैमाने पर मिट्टी की कटाई की जा रही है। अमदाबाद के चोकिया पहाड़पुर के समीप अवैध रूप से मिट्टी का खनन कर बंगाल के ईंट भट्टों तक भेजा जा रहा है। अन्य स्थानों पर मिट्टी का खनन कर स्थानीय बाजारों में बेची जाती है। बलरामपुर प्रखंड के शरीफनगर, महिशाल, लुतीपुर, किरोरा, बिजौल, भिमियाल में अवैध मिट्टी का कारोबार तेजी से फलफूल रहा है।



अमेरिका में कमाए पैसे भारत भेजने पर 3.5% टैक्स लगेगा

►► ‘वन बिग, ब्यूटीफुल बिल एक्ट’ पारित

►► यूएस को सालाना करीब 8 हजार करोड़ मिलेंगे

एजेंसी | वाशिंगटन

अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों को अब अपने देश पैसे भेजने पर अतिरिक्त बोझ झेलना पड़ेगा। 22 मई को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ‘वन बिग, ब्यूटीफुल बिल एक्ट’ पारित किया, जिसके तहत फॉरेन वर्कर्स द्वारा अपने देश पैसे भेजने पर 3.5% टैक्स लगाया जाएगा। पहले यह प्रस्तावित दर 5% थी, लेकिन संशोधन के बाद इसे घटाकर 3.5% कर दिया गया।

क्या है इस बिल का मकसद?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस नीति को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (MAGA) अभियान का हिस्सा बताया है। उनका दावा है कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और घरेलू संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा।



भारत पर क्या पड़ेगा असर?

2023-24 में भारतीयों का रেমिटेंस लगभग 130 बिलियन डॉलर था। इसमें करीब 30 बिलियन डॉलर यानी 23.4% अमेरिका से आया। 45 लाख भारतीयों ने अमेरिका से ये पैसा भेजा। 3.5% टैक्स के लागू होने पर 30 बिलियन डॉलर के रেমिटेंस पर 1.05 बिलियन डॉलर यानी, करीब 8,750 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। ये भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा।

केंद्र को मिलेगा 2.68 लाख करोड़ रुपये का अधिशेष

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय अनुशासन और सरकार की वित्तीय स्थिति को मजबूती देने के तहत बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2.68 लाख करोड़ रुपये का अधिशेष (लाभांश) हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। यह अब तक का सबसे बड़ा अधिशेष हस्तांतरण है, जो पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के 2.1 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 27.4% अधिक है। इस बड़े ट्रान्सफर से केंद्र सरकार को चालू वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा घटाकर 4.4% तक लाने में सहायता मिलेगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 में यह लाभांश केवल 87,416 करोड़ रुपये था। यह निर्णय RBI के



केंद्रीय निदेशक मंडल की 616वीं बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता गवर्नर शक्तिकांत दास (आपके मूल में “संजय मल्होत्रा” लिखा गया है, जबकि RBI के मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास हैं) ने की। बैठक में वैश्विक और घरेलू आर्थिक हालात, भविष्य के जोखिमों और मौद्रिक नीतियों की समीक्षा की गई। RBI ने बैठक में यह भी निर्णय लिया कि (CRB) को मौजूदा 6.5% से बढ़ाकर 7.5% किया जाएगा।

रिलायंस समूह पूर्वोत्तर राज्यों में 75 हजार करोड़ का करेगा निवेश : मुकेश अंबानी



एजेंसी | नई दिल्ली

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को कहा कि उनका समूह पूर्वोत्तर राज्यों में 350 बायोगैस संयंत्र की स्थापना, अपनी दूरसंचार सेवाओं, खुदरा कारोबार एवं स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार पर 75 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगा।मुकेश अंबानी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित ‘राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025’ को संबोधित करते हुए कहा कि रिलायंस जियो पूर्वोत्तर राज्यों के सभी स्कूलों, अस्पतालों, उद्यमों और घरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जोड़ेगा। उन्होंने बताया कि जियो ने पहले ही क्षेत्र की 90 फीसदी आबादी को कवर कर लिया है। जियो में 5 मिलियन से अधिक 5-जी ग्राहक हैं, जबकि इस साल इस संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य है।

मामाअर्थ का शेयर एक दिन में 20% चढ़ा

►► 5 दिन में 27% रिटर्न दिया

एजेंसी | मुंबई

मामाअर्थ की पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर लिमिटेड के शेयर में शुक्रवार, 23 मई को 20% की तेजी रही। ये एक दिन में 55 रुपए चढ़कर 330.19 रुपए पर पहुंच गया। शेयर में यह बढ़त कंपनी के मजबूत तिमाही नतीजों की वजह से हुई। वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में होनासा को 25 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। सालाना आधार यह 18% कम हुआ है। हालांकि कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 13% बढ़कर 534 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की समान तिमाही में यह 471 करोड़ रुपए था।

5 दिन में 23% चढ़ा होनासा कंज्यूमर का शेयर



EBITDA जनरेट किया था। EBITDA मार्जिन भी 7% से गिरकर 5.1% रही है।

Q4FY25 ग्राँस प्रॉफिट मार्जिन Q4FY25 में 70.7% बढ़ा

कंपनी का ग्राँस प्रॉफिट मार्जिन Q4FY25 में 70.7% बढ़ा है। EBITDA यानी अर्निंग बिफोर इंटररेस्ट टैक्स डेप्रििएशन एंड अमॉर्टाइजेशन पिछले साल के मुकाबले 18% गिरकर 27 करोड़ रुपए रहा। Q4FY24 में कंपनी ने 33 करोड़ रुपए का EBITDA जनरेट किया था। EBITDA मार्जिन भी 7% से गिरकर 5.1% रही है।

प्लाइट के टेक ऑफ-लैंडिंग के वक्त बंद रहेंगी खिड़कियां

►► फोटोग्राफी और वीडियो बनाना बैन

►► देश के 4 डिफेंस एयरपोर्ट पर नियम लागू

एजेंसी | नई दिल्ली

देश की रक्षा क्षेत्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने आदेश जारी किया है कि डिफेंस एयरफील्ड से उड़ान भरने और वहां लैंड करने वाली प्लाइट्स में टेकऑफ और लैंडिंग के दौरान खिड़कियां बंद रहनी होंगी। इसके अलावा पैसेंजर्स के लिए फोटो खींचना और वीडियो बनाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।



रक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर आया फैसला

रिपोर्ट के अनुसार DGCA के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि यह देश रक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर 20 मई को जारी किया गया। हालांकि इसकी जानकारी अब सामने आई है। इसका मकसद डिफेंस एरिया की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

कू मंबरर्स को दिए जाएंगे निर्देश

DGCA ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है वे कू मंबरर्स के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेंटिंग प्रोसी जर तैयार करें। मौजूद एयरपोर्ट्स पर उड़ान भरने से पहले या लैंडिंग से पहले पैसेंजर्स को इन नियमों की जानकारी दी जाएगी।

पंजाब की निगाह जीत के 'चौके पर'

- जयपुर में दिल्ली कैपिटल्स की चुनौती का करना होगा सामना
- आखिरी दोनों मैच जीतकर 11 साल बाद तालिका में शीर्ष दो में रहने का प्रयास करेंगे किंग्स

एजेंसी | जयपुर

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 में पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी पंजाब किंग्स की टीम शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी। यह मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। पंजाब की नजर इस मैच सहित आखिरी दोनों मुकाबले जीतकर अंकतालिका में शीर्ष दो में पहुंचने पर है — जो कि वह 11 साल बाद हासिल कर सकती है।

नंबर गेम

► 4 विकेट से हराया था पंजाब ने दिल्ली को पिछले साल खेले गए एक्मत्र मुकाबले में

► 8 विकेट दूर है पंजाब के अर्शदीप सिंह आईपीएल में सी विकेट पूरे करने से

आमने-सामने

कुल मैच : 34
दिल्ली जीता : 16
पंजाब जीता : 17

दिल्ली के लिए सम्मान की लड़ाई

दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत चार जीत से की थी, लेकिन उसके बाद अगले 9 में से सिर्फ दो मैच जीत सकी। टीम अब प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है और अब उसका लक्ष्य सत्र का सम्मानजनक अंत करना होगा। केएल राहुल (504 रन), अभिषेक पोरेल (301 रन) और ट्रिस्टन स्टब्स (282 रन) ही ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने रन बनाए। गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क (14 विकेट) की वापसी से प्रदर्शन बेहतर हो सकता था, लेकिन उनके लीटने से दिल्ली कमजोर हुई। अक्षर पटेल की फिरकी इस सीजन बेअसर रही, जबकि कुलदीप यादव (13 विकेट) को अन्य गेंदबाजों का साथ नहीं मिला।

पंजाब की मजबूत स्थिति

► नए कप्तान श्रेयस अय्यर की नेतृत्व क्षमता में पंजाब किंग्स ने इस सीजन शानदार प्रदर्शन किया है। अय्यर खुद चार अर्धशतकों के साथ 435 रन बना चुके हैं। उनके अलावा प्रभासिमरन सिंह (458 रन) और प्रियांश आर्य (356 रन) ने भी टीम को दमदार शुरुआत दिलाई है। नेहाल वडेरा और मार्कस स्टोइनिस जैसे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों से भी उम्मीदें होंगी। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह (11 विकेट) और युजवेंद्र चहल (13 विकेट) का प्रदर्शन शानदार रहा है। तीन दिन पहले जोश इंग्लिस, आरोन हार्डी और काइल जैमीसन जैसे विदेशी खिलाड़ी भी टीम से जुड़ चुके हैं, जिससे पंजाब की ताकत और बढ़ गई है।



एंजेलो मैथ्यूज ने लिया टेस्ट क्रिकेट से संन्यास

कोलंबो। श्रीलंका क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह अपना आखिरी मुकाबला बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ अगले महीने खेलेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। मैथ्यूज पिछले 17 साल से क्रिकेट का सबसे लंबा प्रारूप खेल रहे हैं। वह श्रीलंका के लिए टेस्ट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

मैथ्यूज ने क्या कहा?

मैथ्यूज ने एक्स पर लिखा, 'प्यारे दोस्तों और परिवार, एक आभार भरे दिल और ढेर सारी यादों के साथ अब समय आ गया है कि मैं क्रिकेट के अपने सबसे पसंदीदा प्रारूप टेस्ट को अलविदा कह दूं। पिछले 17 सालों तक श्रीलंका के लिए क्रिकेट खेलना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान और गर्व की बात रही है। जब कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय जर्सी पहनता है।

मैंने क्रिकेट को अपना सबकुछ दिया है- मैथ्यूज

उन्होंने आगे लिखा, 'मैंने क्रिकेट को अपना सब कुछ दिया है और बदले में क्रिकेट ने भी मुझे बहुत कुछ दिया। यही खेल मुझे वो इंसान बना पाया जो आज मैं हूं। मैं इस खेल का दिल से आभार मानता हूं और उन हजारों श्रीलंकाई फैस का धन्यवाद करता हूं जो मेरे करियर में हर अच्छे-बुरे वक़्त में मेरे साथ खड़े रहे।

जवागल श्रीनाथ होंगे मैच रेफरी

नितिन मेनन को मिला चौथे अंपायर का दायित्व

एजेंसी | नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट टीम भले ही इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल में जगह नहीं बना पाई हो, लेकिन भारत की मौजूदगी मैदान के बाहर जरूर बनी रहेगी। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ को मैच रेफरी के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि अनुभवी अंपायर नितिन मेनन को चौथे अंपायर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जय शाह ने की सराहना

आईसीसी वेयरमैन जय शाह ने कहा, रहमं गर्व है कि हम लॉर्ड्स में होने वाले इस प्रतिष्ठित मुकाबले के लिए इतनी अनुभवी और संतुलित मैच ऑफिशियल्स की टीम घोषित कर पा रहे हैं। यह दो वर्षों की कड़ी प्रतियोगी का समापन है।

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के अंपायर संभालेंगे मैदानी जिम्मेदारी

लॉर्ड्स में 11 से 15 जून के बीच खेले जाने वाले इस खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड के रिचर्ड इलिंगवर्थ और न्यूजीलैंड के क्रिस गाफाने मैदानी अंपायर होंगे। वहीं, अनुभवी रिचर्ड केटलबोरो को टीवी अंपायर नियुक्त किया गया है, जो इससे पहले 2021 WTC फाइनल में भी यही भूमिका निभा चुके हैं।

तीसरे बार इतिहास रचेंगे इलिंगवर्थ

रिचर्ड इलिंगवर्थ लगातार तीसरे डब्ल्यूटीसी फाइनल में मैदानी अंपायर की भूमिका निभाकर इतिहास रचने जा रहे हैं। वहीं, नितिन मेनन 2021 के टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में टीवी अंपायर रह चुके हैं और अब WTC फाइनल में अपना डेब्यू बतौर चौथे अंपायर करेंगे।

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका

गौरतलब है कि WTC फाइनल में गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का सामना पहली बार फाइनल में पहुंची दक्षिण अफ्रीका से होगा। यह मुकाबला टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा ताज जीतने के लिए खेला जाएगा।

बॉलीवुड

'लुका छुपी 2' में नजर आएंगे वरुण धवन

कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की फिल्म 'लुका छुपी' दर्शकों को बेहद पसंद आई थी, वहीं दोनों कलाकारों की केमिस्ट्री ने भी दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब हॉरर यूनिवर्स वाले दिनेश विजान अपनी फिल्म 'लुका छुपी' का सीक्वल बनाने वाले हैं, लेकिन नई फिल्म में न तो कार्तिक होंगे और न ही कृति। कार्तिक की जगह इसमें वरुण धवन ने ले ली है। पीपिंगमून के मुताबिक, निर्माता ने अपनी इस कॉमेडी फिल्म के सीक्वल पर काम शुरू कर दिया है और वह इसे फ्रैंचाइजी की शक्ल देने के लिए तैयार हैं। फिल्म में इस बार नए चेहरे देखने को मिलेंगे। वरुण के साथ

परम सुंदरी

टीजर रिलीज सि

द्वार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की 'परम सुंदरी' इस साल की बहुचर्चित फिल्मों में से एक है। यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पदे पर साथ दिखाई देंगे। तुषार जलोटा के निर्देशन में बनी इस फिल्म का दर्शक बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 'परम सुंदरी' का टीजर 23 मई को राजकुमार राव की 'भूल चुक माफ' के साथ सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया है। 'परम सुंदरी' में पहली बार बनी सिद्धार्थ और जाह्नवी की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। यह फिल्म 25 जुलाई, 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार है। दिनेश विजान इस फिल्म के निर्माता हैं। 'परम सुंदरी' में सिद्धार्थ दिल्ली के एक अमीर या कहे बड़े कारोबार का किरदार निभा रहे हैं। उधर जाह्नवी एक ऐसी लड़की (परम सुंदरी) के किरदार में हैं, जो केरल से ताल्लुक रखती है और पेशे से एक कलाकार है।

स्क्वड गेम 3

का नया पोस्टर आया सामने

कोरियन थ्रिलर वेब सीरीज 'स्क्वड गेम' के तीसरे सीजन का ऐलान पहले ही हो चुका है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में निर्माताओं ने 'स्क्वड गेम 3' का टीजर जारी किया था, वहीं अब इस सीरीज का नया पोस्टर सामने आ गया है, जिसमें ली जूंग जे और पार्क सुंग हून समेत तमाम सितारों की झलक दिख रही है। 'स्क्वड गेम 3' का प्रीमियर 27 जून, 2025 से OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होने जा रहा है। निर्माताओं ने पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'अंत की शुरुआत यहीं है।' यह इस लोकप्रिय कोरियाई थ्रिलर का आखिरी सीजन है। इसमें ली ब्यूंग हून, वी हा जून, इम सी यॉन और कांग हा न्यूल अपने-अपने किरदारों को दोहराते हुए नजर आएंगे। बता दें कि 'स्क्वड गेम' का पहला सीजन 2021 में रिलीज हुआ था।

रवीना टंडन की तमिल सिनेमा में वापसी

अभिनेत्री रवीना टंडन ने अपने करियर में कई छोटी-बड़ी फिल्मों में काम किया है। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने कुछ तेलुगू फिल्मों में भी काम किया था, वहीं कन्नड़ फिल्म में भी उन्हें देखा गया। बंगाली और तमिल फिल्मों में भी उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और अब तमिल सिनेमा में अभिनेत्री की वापसी हो रही है और वो भी पूरे 24 साल बाद। वह तमिल स्टार विजय एंटेनी की फिल्म 'लॉयर' से जुड़ गई हैं। विजय एंटेनी की इस फिल्म से रवीना का पोस्टर सामने आ चुका है और एक्टर-डायरेक्टर ने फिल्म में उनका स्वागत भी कर लिया है। जोशुआ सेथुरामन इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। उन्होंने इस बारे में बताया, 'रमुझ फिल्म 'शूल' में रवीना का अभिनय बेहद पसंद आया था। हमें अपनी फिल्म 'लॉयर' के लिए ऐसी ही अभिनेत्री चाहिए थी। फिल्म में विजय और रवीना दोनों का ही किरदार बहुत दमदार है।

रवीना की 24 साल पहले आई थी ये तमिल फिल्म

रवीना की पहली तमिल फिल्म थी 'साधु', जो साल 1994 में आई थी। पी वासु के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फेल हो गई थी। इसके बाद साल 2001 में रवीना तमिल सिनेमा में लौटीं। उन्होंने कमल हासन के साथ 'आलावंधन' में काम किया, जिसमें मनीषा कोइराला भी थीं।

कोटा कोचिंग: सपने, सुसाइड और सवाल

छात्रों की आत्महत्या पर सुप्रीम कोर्ट सरख्त

एजेंसी | नई दिल्ली

स्टूडेंट सुसाइड के बढ़ते मामलों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोटा (राजस्थान) में हो रही घटनाओं को गंभीर चिंता का विषय बताया गया। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की खंडपीठ ने राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कड़ी टिप्पणी की।

2025 में अब तक 14 आत्महत्याएं, आंकड़े डरावने

सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई 2025 की पिछली सुनवाई में चिंता जाहिर की थी कि इस वर्ष कोटा में अब तक 14 छात्रों ने आत्महत्या की है। 2024 में यह संख्या 17 थी, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 26 तक पहुंच गया था। इससे पहले 2022 में 15, 2019 में 18, 2018 में 20 और 2017 में 7 छात्रों ने जान दी थी। कोविड काल (2020-2021) में कोचिंग बंद होने से आत्महत्या के मामले सामने नहीं आए।

कोर्ट ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देश

बीते कुछ दिनों पहले IIT खड़गपुर के एक छात्र के सुसाइड का मामला और कोटा में एक छात्रा का शव मिलने को लेकर शुक्रवार को कोर्ट सुनवाई कर रही थी। इस दौरान कोर्ट ने राजस्थान सरकार को तीन घटनाओं के संदर्भ में विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।



14 जुलाई 2025 को होगी सुनवाई

कोर्ट ने यह भी कहा कि छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर राज्य की जिम्मेदारी तय की जाएगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई को लेकर 14 जुलाई 2025 की तारीख तय की है। सुनवाई में कोर्ट मानसिक स्वास्थ्य, कोचिंग संस्कृति और सरकारी जिम्मेदारी पर सवाल कर सकती है।

▶▶ राजस्थान सरकार से मांगा जवाब

▶▶ इस साल अब तक 14 से अधिक छात्र कर चुके हैं

कोटा में ही छात्र क्यों खुदकुशी कर रहे : सुप्रीम कोर्ट

कोटा : कभी शैक्षणिक, अब मानसिक दबाव का केंद्र

हर साल कोटा में 85,000 से 1 लाख छात्र देशभर से JEE और NEET की तैयारी के लिए आते हैं। यहां 300 से अधिक कोचिंग संस्थान हैं, जिनका सालाना टर्नओवर कभी 7,000 करोड़ रुपए तक था, लेकिन अब घटकर 3,500 करोड़ रुपए रह गया है। छात्रों पर अत्यधिक दबाव का आलम यह है कि उन्हें रोजाना 18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। हर 15 दिन में टेस्ट, रैंकिंग और दाखिले की सीमित सीटों की दौड़ छात्रों को मानसिक रूप से तोड़ रही है। JEE में करीब 10 लाख छात्रों में से केवल 10,000 को IIT में दाखिला मिलता है, जबकि NEET में 20 लाख में से महज 1.4 लाख को मेडिकल कॉलेज की सीट मिल पाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोचिंग सिस्टम अब एक 'मनी मिटिंग मशीन' बन गया है। एक शिक्षक एक बार में 300 छात्रों को पढ़ाता है, जिससे व्यक्तिगत ध्यान देना असंभव हो गया है। छात्रों की पहचान सिर्फ उनके अंक से तय की जाती है। 2024 में आत्महत्याओं में 38% की गिरावट आई थी।



'अठार यूएस में नहीं बनाया आईफोन तो लगाएं 25% टैरिफ'



ट्रंप ने एपल को फिर दी सीधी धमकी

एजेंसी | वाशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर एपल को धमकी दी है। उन्होंने शुक्रवार को खुली धमकी देते हुए कहा कि अमेरिका में बिकने वाले आईफोन अमेरिका में ही बनने चाहिए। अगर वह अमेरिका से बाहर भारत या अन्य किसी देश में ऐसा करेंगे तो वह एपल पर भारी पड़ेगा। ट्रंप ने टुथ सोशल पर कहा कि अगर प्रौद्योगिकी कंपनी ने ऐसा नहीं किया तो एपल के उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। शुक्रवार को टुथ सोशल पर ट्रंप ने पोस्ट कर यह धमकी दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मैंने बहुत पहले ही एपल के टिम कुक को इस बारे में बता दिया था कि मुझे उम्मीद है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बेचे जाने वाले उनके आईफोन का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा, न कि भारत या किसी अन्य स्थान पर। अगर ऐसा नहीं होता है, तो एपल को अमेरिका को कम से कम 25% टैरिफ का भुगतान करना होगा।'

बढ़ सकती है आईफोन की कीमत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आईफोन की कीमतों में नाटकीय रूप से बढ़ोतरी हो सकती है। इसके चलते एपल की बिक्री और मुनाफे को नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं एपल भी अब अमेजन वालमार्ट और अन्य प्रमुख कंपनियों के साथ हाइड हाउस के निशाने पर आ गई है। दरअसल, ये कंपनियां ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से पैदा हुई अनिश्चितता और मुद्रास्फीति के दबाव का जवाब देने की कोशिश कर रही हैं।

न्यूज़ ग्रीफ

वाईएसआरसीपी नेता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी

मछलीपट्टनम। आंध्र प्रदेश पुलिस ने वरिष्ठ वाईएसआरसीपी नेता और गुडीवाड़ा के पूर्व विधायक केशी वैकटेश्वर राव (कोडाली नानी) के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। कृष्णा जिले के पुलिस अधीक्षक आर गंगाधर राव ने कहा कि पूर्व मंत्री के खिलाफ गुरुवार से सर्कुलर लागू है। उन्होंने कहा कि सर्कुलर गुडीवाड़ा में वाईएसआरसीपी नेता के खिलाफ दर्ज कुछ मामलों से संबंधित है। देश के सभी हवाई अड्डों को जारी किए गए इस सर्कुलर का उद्देश्य कोडाली नानी को देश से भागने से रोकना है।

मैडिकल छात्रा से सामूहिक दुराचार

सांगली। जिले में तीसरे वर्ष की एक मैडिकल छात्रा से उसके साथ पढ़ने वाले दो छात्रों और एक अन्य दोस्त द्वारा कथित सामूहिक दुराचार का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 18 मई की है, जब छात्रा और आरोपियों ने रात करीब 10 बजे थिएटर में फिल्म देखने जाने की योजना बनाई थी। पुलिस अधिकारी के अनुसार, आरोपियों ने फिल्म देखने से पहले छात्रा को एक प्लेट में ले जाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। नशे की हालत में तीनों ने उसके साथ दुराचार किया और धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

एसएमएस अस्पताल में खून चढ़ाने के दौरान गर्भवती की मौत

जयपुर। जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में टोक की एक गर्भवती महिला की खून चढ़ाने के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गलत समूह का खून चढ़ाए जाने के कारण ऐसा हुआ। अधिकारियों के अनुसार 23 वर्षीय वैना को 12 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गर्भवती महिला का हीमोग्लोबिन बहुत कम था और वह तपेदिक सहित कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थी।

पृथ्वी विज्ञान सचिव रविचंद्रन को एक साल का सेवा विस्तार

नई दिल्ली। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान सचिव एम रविचंद्रन का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। रविचंद्रन ने 11 अक्टूबर, 2021 को यह पद संभाला था। वह 60 साल की आयु पूरी होने पर इस महीने के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले थे। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के 22 मई के एक आदेश के अनुसार कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव के रूप में रविचंद्रन का कार्यकाल विस्तार उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख एक जून, 2025 से एक साल के लिए 31 मई, 2026 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कर दिया है।

चार पुलिसकर्मी गिरफ्तार

एजेंसी | फगवाड़ा

पंजाब के फगवाड़ा में ड्रग तस्करी के परिवार से कथित तौर पर रिश्वत लेने के मामले में जिला अपराध जांच एजेंसी (CIA) के चार पुलिसकर्मीयों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में CIA प्रभारी बीसमन साही, सहायक उपनिरीक्षक जसविंदर सिंह, निर्मल कुमार और हेड कांस्टेबल जारूप सिंह शामिल हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) नवीन सिंगला के अनुसार, इन पुलिसकर्मीयों ने ड्रग तस्करी हनी को छोड़ने के लिए उसके परिजनों से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। सिंगला के नेतृत्व में की गई जांच और निगरानी के बाद यह कार्रवाई की गई।



ड्रग तस्करी को बचाने के लिए परिजनों से 2.5 लाख की रिश्वत ली

मुख्य न्यायाधीश के प्रोटोकॉल चूक मामले में याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई याचिकाकर्ता को फटकार, 7000 रुपए का जुर्माना लगाया

एजेंसी | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की महाराष्ट्र यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन के आरोपों पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने इसे "सस्ती लोकप्रियता और प्रचार पाने की कोशिश" करार देते हुए याचिकाकर्ता अधिवक्ता शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी पर 7000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मुख्य न्यायाधीश गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि जब खुद CJI ने अधिकारियों की माफी स्वीकार



कर ली थी और मामले को तूल न देने की अपील की थी, तो ऐसी याचिका दाखिल करने की जरूरत ही नहीं थी। पीठ ने टिप्पणी की, "हम इस प्रकार की प्रथा की कड़ी निंदा करते हैं। सभी संबंधित पक्षों को राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए।"

युवा वकील को चेतावनी, बड़ी सजा से राहत

पीठ ने बताया कि चूंकि याचिकाकर्ता एक सात साल का अनुभव रखने वाला युवा वकील है, इसलिए उस पर भारी जुर्माना नहीं लगाया गया। कोर्ट ने समझाइश देते हुए कहा कि उन्हें CJI द्वारा जारी प्रेस नोट पर ध्यान देना चाहिए था, जिसमें अधिकारियों की माफी के बाद मामले को शांत रखने की अपील की गई थी।

क्या थी याचिका में मांग ?

याचिका में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ प्रोटोकॉल में चूक को लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का दावा था कि CJI की महाराष्ट्र यात्रा के दौरान सुरक्षा और स्वागत की व्यवस्थाओं में लापरवाही हुई।

पंजाब में भ्रष्टाचार केस में आप विधायक गिरफ्तार

एजेंसी | चंडीगढ़

पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक रमन अरोड़ा को अरेस्ट किया गया है। रमन अरोड़ा को पंजाब सरकार के सतर्कता ब्यूरो ने अरेस्ट किया है। पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने राज्य में आप के विधायक रमन अरोड़ा के जालंधर स्थित आवास पर भ्रष्टाचार के एक मामले में शुक्रवार को छापेमारी की। इसके बाद ब्यूरो ने आप विधायक को अरेस्ट किया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। रमन अरोड़ा (54) जालंधर सेंट्रल सीट से विधायक हैं। सूत्रों ने बताया कि यह छापेमारी जालंधर में कुछ अधिकारियों के माध्यम से निर्दोष लोगों को भेजे गए कथित झूठे नोटिस से संबंधित है, जिसमें अरोड़ा की भूमिका जांच के दायरे में आ गई है। संपर्क करने पर आप के प्रवक्ता नील गर्ग ने अरोड़ा के घर पर छापेमारी की पुष्टि की है। राज्य सरकार ने हाल ही में अरोड़ा की सुरक्षा वापस ले ली थी, जिसके बाद विधायक ने मीडिया से कहा था कि उन्हें इस कदम के पीछे के कारण की जानकारी नहीं है। इससे पहले अरोड़ा की सुरक्षा में कथित तौर पर 14 बंदूकधारी तैनात थे।

▶▶ 3 बैगों में भरकर दस्तावेज ले गई विजिलेंस टीम

▶▶ सीएम बोले- अपना हो या पराया भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं



क्यों हुई अरोड़ा की गिरफ्तारी?

पंजाब सतर्कता ब्यूरो (वीबी) ने शुक्रवार को जालंधर सेंट्रल के आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक रमन अरोड़ा को नगर निगम के पूर्व सहायक नगर योजनाकार (एटीपी) सुखदेव वशिष्ठ से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया, जिन्हें पिछले साप्ताह गिरफ्तार किया गया था। अरोड़ा ने कथित तौर पर वशिष्ठ का इस्तेमाल फर्जी नोटिस जारी करने और लक्षित व्यक्तियों से पैसे ऐंठने के लिए किया। उनके खिलाफ शिकायतों के बाद वीबी ने शुक्रवार सुबह अरोड़ा के घर पर छापे मारा। हालांकि वीबी के अधिकारी चुप रहे, लेकिन आप ने इस घटनाक्रम को एक्स पर पोस्ट किया कि भगवंत मान सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई।

बीजेपी विधायक कंवर लाल मीणा की विधानसभा सदस्यता रद्द

20 साल पुराने मामले में मिली थी सजा

एजेंसी | जयपुर

राजस्थान विधानसभा ने शुक्रवार को भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को अयोग्य घोषित कर दिया। यह कार्रवाई 20 साल पुराने एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने और तीन साल की जेल की सजा मिलने के बाद की गई है। अंता विधानसभा सीट से विधायक मीणा की सदस्यता 1 मई 2025 से प्रभावी रूप से रद्द मानी गई है।



सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट पर पिस्तौल तानने का मामला

मीणा को यह सजा उस मामले में मिली, जिसमें उन पर एक उपखंड अधिकारी पर पिस्तौल तानने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, धमकी देने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप था। झालावाड़ जिले की अकलेरा एडीजे कोर्ट ने 14 दिसंबर 2020 को उन्हें दोषी ठहराते हुए तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी।

सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, विधानसभा ने की कार्रवाई

मीणा ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सजा पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी, जोसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने उन्हें दो सप्ताह में आत्मसमर्पण का आदेश दिया था। इसके बाद मीणा ने 21 मई को अकलेरा कोर्ट में सरेंडर कर दिया और फिलहाल जेल में है।

वित्तीय कार्रवाई

पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर घेरेगा भारत

पाकिस्तान को फिर FATF की ग्रे लिस्ट में लाएंगे: सरकार

एजेंसी | नई दिल्ली

भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को घेरने की तैयारी में है। भारत अगले महीने वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) में पाकिस्तान द्वारा टेरेर फंडिंग किए जाने का मुद्दा उठाएगा। साथ ही, विश्व बैंक की आगामी फंडिंग का भी विरोध करेगा। भारत की तरफ से वह सभी साक्ष्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के सामने रखे जाएंगे, जिनसे सबित होता है कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए फंडिंग में लिप्त है।

▶▶ भारत एफएटीएफ में पाकिस्तान को ग्रे सूची में शामिल कराने के लिए देगा पुख्ता साक्ष्य

▶▶ ग्रे सूची में शामिल होने से पाकिस्तान पर लागू होंगी कड़ी शर्तें, रुकेगी वित्तीय सहायता

ग्रे सूची में शामिल होने का मतलब

अगर कोई देश मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने में विफल रहता है या अप्रत्यक्ष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को वित्तीय रूप से बढ़ावा देता है तो ऐसे देश को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। इसके बाद संबंधित देश पर निगरानी बढ़ जाती है। इस सूची में शामिल होने पर अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां तमाम सारी शर्तें लगाती हैं, जिन्हें पूरा करने के बाद वित्तीय सहायता दी जाती है।



पाकिस्तान का ग्रे सूची से जुड़ा पुराना इतिहास

इस सूची में शामिल होने का पाकिस्तान का इतिहास काफी पुराना रहा है। उसे वर्ष 2008 में ग्रे सूची में डाला गया लेकिन 2009 में हटा दिया गया। उसके बाद 2012 से 2015 तक सूची में शामिल रहा। एफएटीएफ ने जून 2018 में पाकिस्तान को फिर से सूची में शामिल डाला। साथ ही, संगठन ने पाकिस्तान को एक कार्य योजना को पूरा करने का निर्देश दिया। पाकिस्तान से कहा गया कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नामित आतंकवादी समूहों, उनके सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ वित्तीय दंड, संपत्ति जब्ती, जांच और कानूनी कार्यवाही करेगी। कुछ शर्तों का पालन होने के बाद अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को सूची से बाहर किया गया, लेकिन इस शर्त के साथ कि पाकिस्तान अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग व आतंकवाद ढांचे के खिलाफ एशिया प्रशांत समूह (एपीजी) के साथ सहयोग बनाए रखेगा।